RESEARCH PAPER

RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
e-ISSN: 2455-3085 | Vol.07 | No.03 | March 2022 | pp. 101-105
*Double-Blind Peer Reviewed/Refereed Journal*

# Afghanistan: An Arena of Global Geopolitics
## अफगानिस्तान : वैश्विक भू–राजनीति का एक अखाड़ा

*Ramesh Kumar

*Research Scholar, Department of Political Science, Jai Narain Vyas University, Jodhpur*

**Abstract**

*Afghanistan is a country located at the meeting point of South, West and Central Asia. It once distinguished itself for its rich cultural heritage and economic equality. But for the last 40 years, due to the mutual competition and interference of global superpowers, it has emerged as the main hot spot of global geopolitics. The direct intervention of the Soviet Union and later the American bloc made Afghanistan the main arena of global geopolitics. By promoting Islamic extremists for their vested interests, the ground was created for a terrorist group like Taliban, which later shook the whole world by linking with a global terrorist organization like Al Qaeda. In the 21st century, a new government was formed for the restoration of democracy and human rights in Afghanistan, despite this it did not succeed in bringing peace and prosperity there. In the changing circumstances, a roadmap for peace is being prepared by involving various stakeholders in the dialogue through the Indra Afghan Peace Dialogue.*

*Despite being perceived as an important part of South Asia, India did not play a significant role in the turmoil in Afghanistan in the 20th century. After the formation of the democratic government under the leadership of Hamid Karzai in 2002, India played its role effectively and made very good efforts for the infrastructure of Afghanistan. Now that the scenario is changing rapidly due to the withdrawal of American troops and the Afghan Peace Dialogue, India also does not let its role be reduced by staying alert. This will be in the interest of both the countries.*

**Keywords:** *Geopolitics, Afghanistan, South Asia, Terrorism, Cold War*

**Abstract in Hindi Language:**

*अफगानिस्तान जो कि दक्षिण, पश्चिम एवं मध्य एशिया के मिलन बिन्दु पर स्थित देश है। यह कभी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा आर्थिक समानता के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखता था। लेकिन पिछले 40 वर्षों से वैश्विक महाशक्तियों की आपसी प्रतिद्वन्द्विता एवं हस्तक्षेप के कारण वैश्विक भू–राजनीति का मुख्य हॉट स्पॉट बनकर उभरा है। पहले सोवियत संघ तथा बाद में अमेरिकी गुट के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप ने अफगानिस्तान को वैश्विक भू–राजनीति का मुख्य अखाड़ा बना दिया। अपने निहित स्वार्थों की खातिर इस्लामिक चरम पंथियों को बढ़ावा देकर तालिबान जैसे आतंकी समूह के लिए जमीन तैयार की जिसने बाद में अलकायदा जैसे वैश्विक आतंकी संगठन के साथ संबंध जोड़कर पूरी दुनिया को हिला दिया। 21वीं सदी में अफगानिस्तान में लोकतंत्र तथा मानवाधिकारों की बहाली हेतु नई सरकार का मुख्य गठन किया गया, बावजूद इसके वहां शांति एवं समृद्धि लाने में कामयाबी नहीं मिली। बदलती परिस्थितियों में इन्द्रा अफगान पीस डायलॉग के माध्यम से विभिन्न हितधारकों को वार्ता में सम्मिलित करके शांति का एक रोडमैप तैयार किया जा रहा है।*

*दक्षिणी एशिया की एक महत्वपूर्ण कथित होने के बावजूद भारत 20वीं सदी में अफगानिस्तान में उठापटक के बीच कोई विशेष भूमिका नहीं निभा पाया। 2002 में हामिद करजई के नेतृत्व में बनी लोकतांत्रिक सरकार के गठन के पश्चात भारत ने प्रभावी रूप में अपनी भूमिका निभाई तथा अफगानिस्तान के आधारभूत ढांचे हेतु काफी अच्छे प्रयास किये। अब जब अमेरिकी सैनिकों की निकासी तथा अफगान पीस डायलॉग से परिदृश्य तेजी से बदल रहा है तो भारत भी चौकन्ना रहकर अपनी भूमिका को कम नहीं होने देता है। यह दोनों देशों के हित में होगा।*

**Keywords:** *भू–राजनीति, अफगानिस्तान, दक्षिण एशिया, आतंकवाद शीतयुद्ध*

**Article Publication**

Published Online: 23-Mar-2022

***Author's Correspondence**

Ramesh Kumar

Research Scholar, Department of Political Science, Jai Narain Vyas University, Jodhpur

ramprabhu151[at]gmail.com

*10.31305/rrijm.2022.v07.i03.017*

© 2022 The Authors. Published by RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

## शोध विस्तारः–

अफगानिस्तानः वैश्विक भू–राजनीति का एक अखाड़ा अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में स्थित है। भू–राजनीति दृष्टि से अफगानिस्तान एक ऐसे जंक्शन पॉइन्ट पर स्थित है जिसकी सीमा दक्षिण एशियाई देशों भारत तथा पाकिस्तान से पश्चिमी एशियाई देशों ईरान से मध्य एशियाई देशों ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के साथ–साथ चीन से लगती है। अफगानिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 6.5 लाख वर्ग किमी. है। जिसमें लगभग 8.5 करोड़ लोग निवासरत है। यहां की मुस्लिम बहुल आबादी विभिन्न नृजातीय समूहों में बटी है, जिसमें पश्तून (42 प्रतिशत), ताजिक (27 प्रतिशत), हाजरा (9 प्रतिशत), उज्बेक (9 प्रतिशत), आईमेक (4 प्रतिशत), तुर्क (03 प्रतिशत), बलोच (2 प्रतिशत) तथा अन्य (4 प्रतिशत) है। हेलमण्ड, काबूल तथा कुर्रम यहां की मुख्य नदियॉ है। काबूल यहां कि राजधानी है।

अपनी उपजाऊ जमीन, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता तथा भू–राजनीतिक अवस्थिति के कारण अफगानिस्तान सदैव ही विदेशी शक्तियों के निशाने पर रहा है। इसी कारण पहले ब्रिटिश, फिर सोवियत संघ तथा बाद में अमेरिका तथा नाटो के हस्तक्षेप से अफगानिस्तान भू–राजनीतिक लड़ाई का प्रमुख स्थल बन गया। इसके अतिरिक्त पड़ोसी देशों यथा मध्य एशियाई देश, ईरान, अरब देशों, भारत, पाकिस्तान तथा चीन के हितों में पारस्परिक टकराव ने भी अफगानिस्तान के विभिन्न नृजातीय समूहों में हिंसक टकराव तथा तालिबान तथा अल कायदा के उभार ने स्थिति को काफी जटिल बना दिया।

## अफगानिस्तान समस्याः पृष्टभूमि–

प्राचीन तथा मध्यकाल में अफगानिस्तान प्रायः एक समृद्ध एवं शांतिमय स्थान के रूप में जाना जाता था। शासन व्यवस्था प्रायः स्थानीय कबीलाई समूहों के पास थी। लेकिन साम्राज्यवाद युग के दुष्प्रभावों से यह क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। एक तरफ ग्रेट ब्रिटेन भारत पर अधिकार करने के पश्चात पश्चिम एवं मध्य एशिया में अपना प्रभाव जमाना चाहता था। इसके लिए यह आवश्यक था। वह पहले अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य जमाए। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के लिए यह भी आवश्यक था कि एशिया महाद्वीप पर अपनी भू–राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए सोवियत संघ के एशिया में बढ़ते प्रभाव को रोका जाये। क्योंकि सोवियत संघ मेकिण्डर द्वारा प्रतिपादित ''हार्टलैण्ड रीजन'' से अपना दायरा बढ़ाकर पश्चिम एशिया तथा अरब सागर तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता था। इस प्रकार पूर्व तथा पश्चिम के इस 'ग्रेट गेम' की जद में अफगानिस्तान पूरी तरह घिर गया।

19वीं सदी के प्रारम्भ में हुई इस प्रतिद्वन्द्विता ने अफगानिस्तान 03 आंग्ल–अफगान युद्धों (1888, 1878 तथा 1919) में धकेल दिया। तृतीय अफगान युद्ध के बाद अफगानिस्तान को काफी हद तक स्वायत्तता प्रदान की। कुछ उठापटक के बाद 1933 में जहीरशाह अफगानिस्तान के शासक बने जो 1973 तक पदासीन रहे। इस दौरान अफगानिस्तान में प्रायः शांति एवं समृद्धि कायम रहीं लेकिन हीरशाह शासक के बाद वहां पर सोवियत प्रभाव में वृद्धि होने लगी तथा 1978 में सोवियत संघ ने प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर दिया तथा अपने 30,000 सैनिक वहां भेज दिए।

यद्यपि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था तथा ब्रिटेन महाशक्ति के रूप में अपना प्रभाव खो चुका था। विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय से द्विध्रुवीय में बदल चुकी थी–पूंजीवादी गुट। जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। जबकि साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ के हाथों में था। इस दौरान सोवियत संघ ने अपने समर्थक शासकों (मोहम्मद दाऊद खां, अब्दुल कादिर, नूर मोहम्मद ताराकी, हकीजुल्लाह आमीन, बाबरक करमाल आदि) तथा सैनिकों की मदद से अफगानिस्तान में अपनी भू–राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की। जिसमें उसे कुछ हद तक सफलता भी मिली। लेकिन इस दौरान वहां समाजवादी नीतियों (यथा सम्पत्ति का पुनर्वितरण, राज्य की अधिकाधिक भूमिका, धर्म पर अपेक्षाकृत कम जोर आदि) के परिणामस्वरूप सोवियत संघ का भारी विरोध होना प्रारम्भ हो गया। रही–सही कसर अमेरिका द्वारा केट्टरपंथि इस्लामिक समूहों को सोवियत विरोधी सहायता एवं उकसावा देकर पूरी से कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप सोवियत संघ अफगानिस्तान में काफी कमजोर पड़ रहा था। इसी बीच 1985 में उदारवादी मिसाईल गार्बाच्योव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सेनाऐं हटाने का वादा किया। फरवरी 1989 तक सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाऐं पूरी तरह से हटा दी। इस प्रकार अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप अपने भू–राजनीतिक हितों को साधने में सफल तो नहीं हुआ लेकिन अफगानिस्तान को अवश्य वैश्विक भू–राजनीति का एक ''हॉट स्पॉट'' बना दिया।

## अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेपः–

1978 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष रूप से सैनिक भेजकर हस्तक्षेप करके तथा साम्यवाद समर्थित सरकार की ताजपोशी करके इस क्षेत्र में अपनी भू–राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए तो उसके घुर विरोधी सोवियत संघ अमेरिका का परेशान होना लाजिमी थी। ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका तथा उसके सहयोग देशों ने

अफगानिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथियों जिन्हें मुजाहिर कहा जाता था, को सहायता देकर भडकाना शुरू किया, ताकि सोवियत प्रभाव को वहां से समाप्त किया जा सके, अन्ततः 1988 के प्रारम्भ में इसको सफलता मिल ही गई जब सोवियत गुट ने अपने सैनिकों की पूर्णतया निकासी कर ली।

### तालिबान का अभ्युदय एवं कट्टर इस्लामिक शासन प्रणाली–

सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिकी गुट द्वारा पोषित मुजाहिदों तथा अन्य धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा 1994 में 'तालिबान' का गठन किया गया। 'तालिबान' परतों भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी (छात्र) जो इस्लामिक कटरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते है। यह अफगानिस्तान में शरीयत के आधार पर पूर्णतया कठोर इस्लामिक शासन स्थापित करने का इच्छुक था। 1996 में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति बुर हानुहीन रब्बानी के कार्यकाल में राजधानी काबुल पर अधिकार कर लिया जो 2001 तक जारी रखा। इस दौरान तालिबानी शासन ने काफी कठोर इस्लामिक नियमों को अपनाया, जैसे अंग–भंग, बुर्का नहीं पहनने पर सख्ती, गैर इस्लाम अनुयायियों के साथ अमानवीय व्यवहार, वामियान में बौद्ध स्मारकों की तोड़फोड़ आदि। इस दौरान तालिबान तथा अलकायदा ने आपसी गठबन्धन करके काफिरों (गैर–मुस्लिम) के खिलाफ हमले प्रारम्भ कर दिए। इसी में एक महत्वपूर्ण हमला 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाईट हाउस, रक्षा विभाग पेंटागन तथा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर किया था। ये हमले ओसामा बिन लादेन के नैतृत्व में अल कायदा ने किए थे जिसको तालिबान ने समर्थन दिया हुआ था।

### आतंक के खिलाफ लड़ाई तथा अमेरिका का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप–

2001 का आतंकी हमला अमेरिका की प्रतिष्ठा तथा सम्प्रभुता पर गहरा प्रहार था। इसने न केवल अमेरिका वरन् समूचे विश्व को हिला कर रख दिया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अलकायदा तथा तालिबान सहित आतंकी समूहों के खिलाफ अपनी रणनीति प्रस्तुत की जिसे ''आतंक की खिलाफ युद्ध'' नाम दिया गया। 2001 में अफगानिस्तान में ऑपरेशन ''एन्डयुटिंग फ्रीडम'' के माध्यम से प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप करके आतंकियों पर हमले प्रारम्भ कर दिये। कालान्तर में अपने नाटों सहयोगियों के साथ मिलकर 15000 से अधिक सैनिक भी तैनात कर दिए। कुछ वर्षों में तालिबान तथा अलकायदा को काफी छोटे क्षेत्र तक सीमित कर दिया। 2011 में पाकिस्तान की सीमा में धुलकर 2001 के अमेरिकी हमलों के मुख्य गुनाहगार ओसामा बिन लादेन को मार गिराया।

अफगानिस्तान में आतंकवाद के खात्मे, मानवाधिकारों की रक्षा तथा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की योजना के साथ हामिद करजई को राष्ट्रपति पद पर आसीन कराया। करजई 2014 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। 2014 में उनकी जगह अशरफ गनी राष्ट्रध्यक्ष बने। इस दौरान अफगानिस्तान में हालत काफी हद तक सुधरे, लेकिन शांति स्थापना का सपना सदैव अधूरा ही रहा। तालिबान हमेशा ही आक्रमण करता रहा है।

यद्यपि अमेरिका अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में सफल तो नहीं हो पाया लेकिन वह अफगानिस्तान को भू–राजनीति का विश्व बिन्दू बनाकर मध्य पूर्व तथा अरब देशों में अपने भू–राजनीतिक हितों का साधने में काफी हद तक सफल रहा है। अफगानिस्तान के माध्यम से उसने न केवल ईरान तथा सीरिया को प्रतिसंतुलित करने में सफलता हासिल की बल्कि अरब देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारते हुए वहां अपने सैन्य बेस स्थापित कर लिए, इसके साथ–साथ ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने भी काफी हद तक सफल रहा।

### अफगानिस्तान में बदलती परिस्थितियॉः–

पिछले 4 दशकों में दक्षिण एशिया का यह छोटा सा देश वैश्विक रंगमंच के तनाव का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बना हुआ है। पहले जब सोवियत संघ ने अपने भू–राजनीतिक हित साधने हेतु इस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया तब अमेरिकी गुट ने सोवियत गुट को प्रति संतुष्टि करने हेतु कटरपंथी गुजाहिंदों को समर्थन दिया। कालान्तर में जब ये मुजाहिंद जब अमेरिका के ही खिलाफ हो गए तो लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों की बहाली के नाम पर वहां सैनिक भेजकर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर दिया। इस प्रकार पिछले 40 वर्षों में अफगानिस्तान सोवियत संघ, अमेरिका, तालिबान तथा अन्य बाहरी शक्तियों की आपसी प्रति द्वन्द्विता का अखाड़ा मात्र बनकर रह गया। इन सबके बावजूद शांत, समृद्ध एवं खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाब अधूरा ही है।

इस प्रकार अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा जारी हमलों, मानवाधिकार हनन के आरोपो, नाटो सहयोगियों द्वारा सैनिक वापिस बुलाने का दबाव तथा अमेरिकी राष्ट्रपतियों द्वारा ओबामा तथा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अफगानिस्तान से सैनिक वापिस बुलाने की घोषणा इत्यादि के फलस्वरूप अमेरिका तथा उसके सहयोगियों ने 2014 से अमेरिकी सैनिकों की निकासी प्रारम्भ की गई। वर्तमान में करीब 6–8 हजार अमेरिकी सैनिक वहां बचे है। जिनकी निकासी वर्ष 2021 के अन्त तक प्रस्तावित है।

### इन्ट्रा अफगान पीस डायलॉग–

यह वैश्विक समुदाय द्वारा समर्थित शांति वार्ता है जिसको अफगान सरकार, तालिबान तथा अन्य स्थानीय हित धारक आपसी बातचीत द्वारा अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध प्रयासरत है। इसके लिए कतर की राजधानी दोहा में तथा रूस की राजधानी मास्कों में सम्मेलन वर्ष 2020 में आयोजित किये जा चुके है। इन्ट्रा अफगान पांस डायलॉग हेतु पूर्व शर्तों के साथ प्रारम्भ की गई है।

- सीजफायर लागू करना तथा हिंसा रोकना।
- शांति हेतु निरन्तर इन्ट्रा अफगान वार्ता का आयोजन करना।
- तालिबान अलकायदा जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से अपने संबंध समाप्त करे।
- अमेरिका तथा उसके सहयोगी अफगानिस्तान से अपने सैनिक वापिस बुलाऐगें।
- इसमें बाद में 02 बाते और भी जोड़ी गई थी, जो इस प्रकार थी–
- निकट भविष्य में तालिबान को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबन्धों से मुक्ति दिलाने के प्रयास किए जाएगें।
- तालिबान 1000 अफगान सैनिकों की रिहाई करेगा तथा अफगानिस्तान 5000 तालिबानों आतंकियों को रिहा करेगा।

इन्ट्रा अफगान पीस वार्ता को सफल बनाने तथा अफगानिस्तान में शांति स्थापना हेतु 6 + 2 + 1 देशों का एक समूह भी बनाया गया है जिसमें 6 अफगानिस्तान के पड़ोसी देश चीन, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान +2 में सोवियत रूप तथा अमेरिका तथा स्वयं अफगानिस्तान शामिल है।

### अफगानिस्तान में भारत की भूमिका–

अतीत में अफगानिस्तान भारत का एक अभिन्न भाग रहा है। दोनों की साझा तथा समृद्धि ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विरासत रही है के दौर में भारत की तरह अफगानिस्तान ने भी स्वतंत्रता के बाद शीतयुद्ध गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया तथा दोनों के संबंध प्रायः मधुर रहे। लेकिन 1978 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने भारत के लिए भी स्थितियॉ को जटिल कर दिया। इससे अफगानिस्तान शीतयुद्ध का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया। इसके पश्चात वहां पर मुजाहिंदों को अमेरिका द्वारा समर्थन, तालिबानी शासन तथा अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण भारत की भूमिका काफी सीमित हो गई।

कालान्तर में जब तालिबानी आतंकियों ने कंधार काण्ड के द्वारा भारतीय यात्री हवाई जहाज को अपहरण करके आतंकियों को रिहाई करवाया गया तब से भारत अफगानिस्तान में सक्रिय मोड पर आया। 2002 में जब तालिबान शासन के स्थान पर मोहम्मद हामिद करजई राष्ट्रपति बने तो भारत के लिए स्थितियॉ कुछ अनुकूल हो गई। पिछले 02 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में अपनी सांस्कृतिक कूटनीति तथा आधारभूत परियोजनाओं (संसद भवन का निर्माण, सलमा बांध निर्माण, जारान्ज डेलराम हाइवे, शहतूत बांध आदि) के द्वारा वहां के विकास तथा समृद्धि में निरन्तर योगदान देकर स्वयं को एक महत्वपूर्ण हितधरक के रूप में खड़ा कर चुका है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति करजई एवं अब्दुल गनी भी भारत को अफगानिस्तान का बड़ा भाई बता चुके है।

लेकिन अमेरिका द्वारा सैनिकों की निकासी तथा इन्ट्रा अफगान वार्ता के जरिए तालिबान से बातचीत की शुरूआत से परिदृश्य बड़ी तेजी से बदल रहा है। भारत के लिए परेशानी की बात यह है कि तालिबान से वार्ता करना तथा सत्ता में उसकी भागीदारी देना। क्योंकि तालिबान सदैव ही कट्टर इस्लामिक शरीयत के आधार पर शासन स्थापित करना चाहता है जबकि भारत उदार लोकतांत्रिक तथा मानवाधिकार समर्थक सरकार की स्थापना के पक्ष में रहा है।

इन बदलते परिदृश्य में भारत के लिए यही बेहतर होग कि वह इन्ट्रा अफगान वार्ता में मजबूती से भाग ले तथा अफगानिस्तान में अपने द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों को सशक्त तरीके से प्रस्तुत करे। तालिबान के इतिहास को मजबूती से प्रस्तुत करके विश्व समुदाय को आगाह करे कि तालिबान को लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने हेतु बाध्य करे। साथ ही साथ वहां निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के साथ सरकार गठन पर बल दे। नवगठित सरकार के साथ अपने संबंधों को मजबूती देकर सशक्त एवं समृद्ध अफगानिस्तान के साथ–साथ अफगानिस्तान, मध्य एशिया, ईरान तथा अरब देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके अपने भू–राजनीतिक हितों को भी साधा जा सके तथा पाकिस्तान एवं चीन को प्रति संतुलित किया जा सके।

## निष्कर्ष–

अफगानिस्तान जो कभी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश था तथा समृद्धि का एक प्रतीक था। लेकिन साम्राज्यवाद तथा बाद में शीतयुद्ध के दौर में महाशक्तियों की आपसी प्रतिद्वद्विता ने इसे वैश्विक भू–राजनीति का 'शेटर बेल्ट' बना दिया। अपने निजी हितों को साधने हेतु आतंकवादियों तक को समर्थन दिया गया तथा मानवाधिकारों का खुलेआम हनन किया गया। लगभग 4 दशकों की हिंसा तथा अशांति ने अफगानिस्तान को आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से निर्बल तथा पराश्रित कर दिया।

सोवियत संघ तथा बाद में अमेरिका गुट द्वारा वहां शांति स्थापना, लोकतांत्रिक शासन तथा मानवाधिकारों की बहाली के नाम पर अपने भू–राजनीतिक हितों को साधने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ चरमपंथी तालिबान ने स्थितियों और भी प्रतिकूल कर दी।

हालिया दौर में इन्ट्रा अफगान पीस डायलॉग द्वारा अफगानिस्तान में शांति स्थापना का रोडमेप प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन इसमें तालिबान जेसे चरमपंथि समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका फिर से संशय की स्थिति उत्पन्न कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में भारत जैसे क्षेत्रीय भागीदारों को आगे आकर मजबूती से सशक्त एवं समृद्ध अफगानिस्तान हेतु पैरवी करनी चाहिए, जो लोकतांत्रिक, मानवाधिकारों का समर्थक, सर्वाधर्म समभाव तथा आंतरिक रूप से मजबूत हो।

## संदर्भ सूचीः–


1. रूबिन आर. बार्नेट, ''अफगानिस्तान : फ्रॉम द कोल्ड वार थ्रू द वार ऑन टेरर, 2013, ऑक्सफोर्ड यूनिर्वसिटी प्रेस पब्लिकेशन।''
2. ली, जोनाथन, ''अफगानिस्तान : ए हिस्ट्री फ्रॉम 1260 टू द प्रजेन्ट'', 2018, रिएक्शन बुक्स लि., लंदन।
3. डेलरिम्पल, विलियम, ''रिटर्न ऑफ ए किंग : द बैटल ऑफ अफगानिस्तान'' ब्लूम्सबरा पब्लिकेशन, लंदन।
4. रीडल, बूस, ''व्हार वी वॉन : अमेरिकाज स्वीक्रेट वॉर इन अफगानिस्तान, 1979–89'' ब्रूकिंग इन्स्टीट्यूशन प्रेस, वाशिंगटन, 2014
5. वीजबॉम भारविन, ''द 3 माइथ दैड सैन्क द अफगान पीस प्रोसेस,'' द डिल्लोमेंट मैग्जीन, अगस्त, 2021
6. वेबसाइड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नरल अफेयर्स।